साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 08-14 अगस्त 2022, वर्ष-8, अंक-18

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

2018 से अब तक हजारों किसानों को राशि का इंतजार

केसीसी से काटा बीमा प्रीमियम, 5 साल बाद भी नहीं मिला क्लेम

भोपाल। किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से फसल बीमा का प्रीमियम काटने के बाद भी क्लेम नहीं मिला। इसमें कई बैंकर्स की मनमानी के कारण किसानों को पांच साल से फसल बीमा राशि नहीं मिली है। प्रशासन ने ऐसे किसानों की समस्या निराकरण के लिए कृषि विभाग और एलडीएम की अगुवाई में संयुक्त कर्मचारियों की टीम गठित की है। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के दौरान अधिकारियों को जानकारी मिली है कि कई बैंकर्स ने वर्ष 2018 में फसल बीमा किसानों के केसीसी किया। कुछ बैंकर्स ने किसानों के फसल बीमा की जानकारी पोर्टल पर इंट्री नहीं की। इसमें ऐसे भी किसान किसान हैं जिन्हें अभी तक क्लेम नहीं मिला है। ऐसे सैकड़ों किसान अभी भी बैंकर्स का चक्कर काट रहे हैं। कुछ तो किसान परेशानी को देखते हुए फसल बीमा से दूर हो गए। कृषि अधिकारियों का तर्क है पांच साल पहले फसल बीमा करने वाले कई बैंकर्स जानकारी नहीं दे रहे हैं। कृषि अधिकारियों का दावा है कि एक साल पहले का क्लेम सभी किसानों को मिल चुका है।

74 हजार किसानों का जमा हुआ प्रीमियम

वर्ष 2019-20 में पोर्टल पर इंट्री से किसानों का क्लेम मिला है। चालू वर्ष में अभी तक कुछ किसानों को बीते सीजन की फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है। ऐसे किसानों को फसल बीमा का लाभ देने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखाकर अधिकारी भूल गए हैं। जबकि प्रदेश के 74 हजार किसानों का प्रीमियम जमा हुआ था।

सीएम शिवराज की दो टूक-शिकायत न आए, प्रदेश में 30 सितंबर तक मूंग-उड़द की होगी खरीदी

मूंग-उड़द की खरीदी में न हो भ्रष्टाचार

» सरकार ने उपार्जन के लिए 741 खरीदी केंद्र बनाए

» सात हजार 275 रुपए क्विंटल मूंग की खरीदी करेगी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की खरीदी 8 अगस्त से 30 सितम्बर तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपार्जन में भ्रष्टाचार की संभावना नहीं हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि व्यापारियों द्वारा किसानों के नाम पर मूंग और उड़द का विक्रय किया जाए तो उसकी खरीदी किसी भी कीमत पर नहीं की जाए। किसानों से ही मूंग और उड़द का उपार्जन किया जाए। छोटे किसानों की शत-प्रतिशत मूंग और उड़द के उपार्जन को प्राथमिकता दें। जहां तक संभव हो इलेक्ट्रानिक तोल कांटों से तुलाई की जाए। खरीदी लक्ष्य के अनुसार सुनिश्चित हो। विपणन वर्ष 2022-23 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7 हजार 275 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6 हजार 300 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

741 खरीदी केन्द्र

बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि मूंग एवं उड़द के उपार्जन के लिए 741 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। अभी 32 जिलों में मूंग फसल के लिए 2 लाख 34 हजार 749 कृषकों द्वारा 6 लाख एक हजार हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया गया है। इसी तरह 10 जिलों में उड़द फसल का 7 हजार 329 कृषकों द्वारा 10 हजार हेक्टेयर रकबे का उपार्जन के लिए पंजीयन कराया गया है। भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम की गाईडलाइन के अनुसार प्रतिदिन प्रति कृषक 25 क्विंटल मात्रा का उपार्जन किया जाना प्रस्तावित है।

» छह हजार 300 रुपए क्विंटल उड़द की खरीदी होगी

» व्यापारियों से किसी भी कीमत पर खरीदी न हो

» छोटे किसानों की मूंग-उड़द को दें प्राथमिकता

5200 ग्रामों में होगी प्राकृतिक खेती

इधर, सरकार ने राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश के किसानों को एक देशी गाय के पालन पर अनुदान और प्रत्येक जिले के 100 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना संपूर्ण मप्र में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया। योजना के अंतर्गत 52 जिलों में 100 ग्रामों का चयन कर कुल 5200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक ग्राम से 5, इस प्रकार कुल 26 हजार प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों का चयन कर उन्हें गौ-पालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के रूप में 900 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों का एक पोर्टल/एप तैयार किया जाएगा।

किसान होंगे प्राकृतिक प्रेरक

इस पर पंजीकृत कृषकों को मास्टर ट्रेनर एवं ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का मानदेय 1 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा और वे प्राकृतिक प्रेरक कहलाएंगे। प्रशिक्षण पर 400 रुपए प्रति कृषक प्रति दिन का व्यय प्रावधानित किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए 39 करोड़ 50 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, जो राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। प्रशासकीय विभाग ने प्रथम चरण में 26 हजार कृषकों के लिए 900 रुपए प्रतिमाह के मान से 1 वर्ष के लिए 28 करोड 08 लाख के व्यय की स्वीकृति दी है।

गौशाल के गोबर से विदेशी कंपनी कमाएगी करोड़ों रुपए, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार

ऑस्ट्रेलियाई कंपनी मुरैना में लगाएगी बायोगैस प्लांट

मुरैना। जागत गांव हमार

ऑस्ट्रेलिया की कंपनी भारत में गाय के गोबर से करोड़ों रुपए कमाने का प्लान बना रही है। ये है ऑस्ट्रेलियाई कंपनी एडीएल इंजीनियरिंग बायो एनर्जी। एडीएल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के मुरैना में बायोगैस प्लांट लगाने जा रही है। इससे यह करोड़ों रुपए की कमाई करेगी। गौशाला में बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। फिर गाय के गोबर से बायो-सीएनजी तैयार की जाएगी। गौशाला में स्थापित होने वाले बायोगैस प्लांट से रोजाना 624 किलोग्राम बायो-सीएनजी गैस का उत्पादन किया जाएगा। इस पूरी परियोजना का खाका तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द इसे शुरू किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी बायोगैस संयंत्र स्थापित करने जा रही है। उसे इस पूरी परियोजना से सालाना लगभग छह करोड़ रुपए इनकम की उम्मीद है।

मुरैना निगम को मिलेगा सालाना एक करोड़

एडीएल इंजीनियरिंग का दावा है कि कंपनी इस बायोगैस प्लांट से हर साल छह करोड़ बायो-सीएनजी का उत्पादन करेगी। इससे ये अच्छा मुनाफा कमा पाएगी। कंपनी के मुनाफे में से कुछ हिस्सा मुरैना नगर निगम को जाएगा। 6 करोड़ रुपए के सालाना प्राफिट में ये करीब एक करोड़ दो लाख की रकम मुरैना नगर निगम को दी जाएगी। इससे मुरैना नगर निगम को भी फायदा होगा।

लोगों को मिलेगा रोजगार

बायोगैस प्लांट के शुरू होने से स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। इससे उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय लोगों के बीच बेरोजगारी कम होगी। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी की तरफ से मुरैना नगर निगम से संपर्क किया गया है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। जल्द ही इसके नतीजे सामने आ सकते हैं।

बायोगैस प्लांट लगाने का प्रपोजल आया है, लेकिन अभी यह फाइनल नहीं हुआ है। कंपनी अस्ट्रेलिया की है, लेकिन केरल के अल्वर्ट ने इस पर काम करने की रुचि दिखाई है। हां यह जरूर है कि कंपनी बायोगैस के साथ गौशाला का संचालन भी करेगी। अगर प्रपोजल फाइनल हो जाएगा तो इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

संजीव जैन, कमिश्नर, नगर निगम, मुरैना

तेरह लाख किसानों को डीबीटी से दी सिंचाई की 385 करोड़ सब्सिडी

भोपाल। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र के 13 लाख 25 हजार किसान के खातों में सिंचाई के लिए जुलाई माह की सब्सिडी राशि 385 करोड़ 98 लाख जमा की गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को योजना की अनुदान राशि और जानकारी पारदर्शिता के साथ समय पर उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी कारगर साबित हो रही है। डिजिटाईजेशन की दिशा में यह बहुत अच्छा कदम है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि कंपनी क्षेत्र के सभी पंद्रह जिलों के किसानों के खातों में राज्य शासन की ओर से सिंचाई कार्य के लिए दी जाने वाली सब्सिडी जमा कराई जा रही है।

डीबीटी के लिए मैराथन प्रयास| डीबीटी की तैयारी के लिए बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने एक वर्ष तक सघन प्रयास किए। किसानों के मोबाइल नंबर, आधार नंबर, खाता और खसरा आदि जुटाए गए। तेरह लाख किसानों के घरों और खेतों पर जाकर सभी जानकारी एकत्र की गयी। तीन चरणों में इनका विधिवत परीक्षण किया गया। जिला प्रशासन से भी मदद ली गई।

नींबू के 180 पौधों से हर साल कमा रहे 2.5 से तीन लाख

मिर्च वाले निमाड़ में नींबू ने बनाया मालामाल

खरगोन जिले के किसान ने अब 5 एकड़ में रोपे 400 पौधे

खंडवा। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले का नुरियाखेड़ी गांव। यहां रहने वाले 35 साल के कृष्णपाल सिंह तोमर किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। खेती-किसानी का जिम्मा आ गया। 40 एकड़ जमीन में पहले की तरह ही गेहूं, सोयाबीन और मिर्च की खेती करते रहे। ट्रेडिशनल खेती से लागत तक निकलना मुश्किल हो गया। कर्ज बढ़ता गया। खेती से होने वाली आमदनी दिनों-दिन कम होती जा रही थी। हालात बदलने के लिए कृष्णपाल ने बागवानी करने का निर्णय लिया। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसान ने बताया कि मैंने सोयाबीन की खेती में लगने वाला खर्च निकालने के लिए खेत के एक हिस्से में बागवानी का निर्णय लिया। 10 साल पहले ट्रेडिशनल खेती से हटकर सरकारी मदद से सिर्फ एक एकड़ जमीन में नींबू के 180 पौधे लगाए।

इस बगीचे से सालाना 2.50 से तीन लाख तक की कमाई होने लगी। 40 एकड़ जमीन में सोयाबीन समेत अन्य फसलों की लागत निकलनी शुरू हो गई। पहले की तरह अब खाद, बीज और दवाओं के लिए बैंक या साहूकार से कर्ज नहीं लेना पड़ रहा। पहले ट्रेडिशनल खेती करने के दौरान लागत भी नहीं निकल पाती थी, बल्कि कर्ज अलग से लेना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होता। मेरे बगीचे के ज्यादातर नींबू खेत से ही बिक जाते हैं। बाकी जो बचते हैं, उन्हें खंडवा मंडी में भेज देता हूं। नींबू का भाव इस साल 300 रुपए किलो तक रहा। कम से कम 50 रुपए प्रति किलो तक का भाव मिला।

जैविक खाद के लिए बकरी पालन किया

कृष्णपाल सिंह ने बताया कि नींबू के लिए किसान मित्र ने बकरी के गोबर वाले खाद को उपयोगी बताया। पहले तो बाजार से बकरी का गोबर लाते थे, लेकिन जरूरत बढ़ती गई तो खुद ही बकरी पालन शुरू कर दिया। अब 40 बकरियां पाल रहे हैं। इनके गोबर का उपयोग नींबू के खेत के खाद के रूप में करते हैं। अब स्थिति यह है कि बागवानी के अलावा खेत के लिए जैविक खाद घर पर ही तैयार हो जा रही है। बकरी के गोबर से बने खाद पौधे को स्वस्थ रखने और पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। बकरी के गोबर की ओर कीड़े आकर्षित नहीं होते हैं। यह खाद गंधहीन होती है। मिट्टी के लिए फायदेमंद होती है। बकरी के गोबर की खाद में घोड़े और गाय के खाद की तुलना में नाइट्रोजन में अधिक होती है। इसमें औसतन 1 टन में 22 पाउंड नाइट्रोजन होता है। गाय की खाद में 1 टन में केवल 10 पाउंड नाइट्रोजन की मात्रा होती है।

ट्यूब पर सीखा ऑर्गेनिक खेती करना

कृष्णपाल सिंह के मुताबिक खेती की नई तकनीकों के बारे में पढ़ना शुरू किया। रोजाना यूट्यूब पर ऑर्गेनिक खेती को लेकर वीडियोज देखे। फायदा यह हुआ कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करने लगे। इससे दोहरा लाभ मिला। एक तरफ लागत कम हुई, तो दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ने के साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ गई। केमिकल का इस्तेमाल किए बिना कम लागत में गुणवत्तापूर्ण पैदावार होती है। जैविक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड या खरपतवार नाशक की बजाय गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद, हरी खाद, वैक्टीरिया कल्चर और जैविक कीटनाशक का उपयोग करते हैं।

इस तरह करते हैं नींबू की खेती

कठोर मिट्टी को छोड़कर किसी भी मिट्टी पर नींबू की खेती की जा सकती है। इसके पौधे लगाने के लिए बेहतर समय जुलाई से अगस्त के बीच होता है। हम ग्राफ्टेड और बीज दोनों ही तरीके से नींबू का प्लांट लगा सकते हैं। एक एकड़ में तकरीबन 120 पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे के बीच की दूरी 5 मीटर से कम ना रखें। पौधा लगाते समय गोबर की कम्पोस्ट खाद का उपयोग करें। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सबसे बढ़िया तरीका है। देशी नींबू तीन साल में फल देने लगता है। 30 से 35 साल तक इनकी आयु होती है। इसके साथ ही समय-समय पर निंदाई और गुड़ाई करनी होती है।

ग्राफ्टिंग तरीके से करते हैं खेती

किसान कृष्णपाल सिंह के अनुसार प्लांटिंग के लिए बरसात का मौसम सबसे बेहतर होता है। जुलाई से अगस्त के बीच पौधे रोपे जाते हैं। आमतौर पर नींबू के पौधे तीन से चार साल में फल देने लगते हैं, लेकिन अगर आप कमर्शियल लेवल पर नींबू की बागवानी करते हैं, तो आपको ग्राफ्टिंग तरीके से तैयार पौधे लगाने चाहिए। इस तरह के पौधे एक साल के भीतर तैयार हो जाते हैं। कई प्लांट तो साल में तीन बार भी फल देने लगते हैं। जहां तक सिंचाई की बात है, गर्मी के सीजन में हर 10 दिन के अंतराल पर और सर्दी के दिनों में 20 से 25 दिन के अंतराल पर इसके पौधों में पानी डालना चाहिए।

दो एकड़ में नींबू का दूसरा बगीचा

बागवानी का विस्तार करते हुए मैंने एक अमरूद का बगीचा लगाया। इसकी मेड़ों पर आम के पौधे लगा दिए हैं। एक एकड़ में नींबू से होने वाली आय से इसी साल 5 एकड़ में नींबू का दूसरा बगीचा भी तैयार कर लिया है। इस बगीचे में नींबू के 400 पौधे लगाए हैं। पहले हम सोयाबीन और गेहूं की फसल लगाते थे, लेकिन अब नींबू के साथ हल्दी की बोवनी कर रहे हैं।

प्रमुख सचिव खाद्य किदवई ने लिखा कलेक्टरों को पत्र

पहले मूंग का उपार्जन-भंडारण सरकारी गोदाम में होगा

मूंग उपार्जन और भंडारण में पारदर्शिता के मापदंड तय

राज्य शासन द्वारा मूंग उपार्जन एवं भंडारण के लिए गोदाम का चयन पूरी पारदर्शिता से करने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। मूंग भंडारण के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप वेयर-हाउस के चयन के संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टर को पत्र लिखा है। प्राथमिकता के क्रम में सर्वप्रथम मूंग का उपार्जन और भंडारण शासकीय गोदाम में किया जाएगा।

भोपाल। जागत गांव हमार

शासकीय गोदामों में उपलब्ध भंडारण क्षमता की जानकारी आपूर्ति अधिकारी कलेक्टर को उपलब्ध कराएंगे एवं जानकारी की सत्यता का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। शासकीय गोदामों में अनुमानित उपार्जन के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता न होने की स्थिति में शेष भंडारण एवं उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम के ऐसे अनुबंधित निजी गोदामों में किया जा सकेगा, जिनके परिसर में वे-ब्रिज की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे गोदाम, जिनके 4 किलोमीटर की परिधि के भीतर वे-ब्रिज की सुविधा उपलब्ध हो और इसके बाद ऐसे निजी गोदाम, जो मुख्य राष्ट्रीय/राज्य/जिला मार्ग पर स्थित हों, को भंडारण के लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य निजी गोदाम भंडारण के लिए उपयोग में लिए जा सकेंगे।

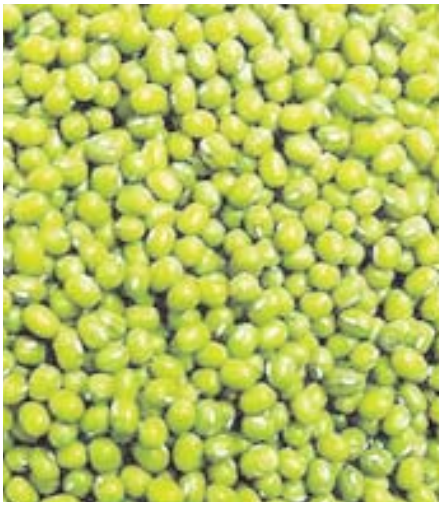

लायसेंसधारी को प्राथमिकता

भंडारण के लिए 2 या अधिक निजी अनुबंधित गोदाम प्राथमिकता क्रम में एक समान स्थिति में हों, तो उस गोदाम को वरीयता दी जाएगी, जो पीएमएस का कार्य नागरिक आपूर्ति निगम से अनुबंधित एजेंसी को सौंपने के लिए लिखित रूप से सहमति देगा। गोदाम समान स्थिति में होने की दशा में पहले लायसेंस प्राप्त गोदाम को प्राथमिकता दी जाएगी।

चस्पा होगी सूची

भंडारण के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार कलेक्टर चयनित गोदामों की प्राथमिकता क्रम में सूची तैयार कर उल्लेख करेंगे कि चयन किस प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया गया है। उक्त सूची वेबसाइट एवं संबंधित कार्यालय के नोटिस-बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। कोई व्यक्ति इस संबंध में जानकारी मांगता है अथवा कोई आपत्ति दर्ज कराता है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर निराकरण किया जाएगा।

रीवा। रीवा शहर के कोठी कंपाउंड स्थित फूलों का बाजार वेटरनरी विभाग के रिटायर डॉ. रामनारायण पांडेय की देन है। उनके बेटे अमित कुमार पांडेय ने बताया कि शहर से महज 5 किमी दूर बैसा हमारा पुस्तैनी गांव है। यहां 1985 में मेर पिता ने दो एकड़ में फूलों की नर्सरी तैयार की। शुरुआत सुंगधा और रजनीगंधा फूल से हुई। धीरे-धीरे हमारे खेतों में खिलने वाले फूलों की महक शहर तक पहुंची। उस समय फूल तो कई लोग लेना चाहते थे, लेकिन बाजार नहीं था। ऐसे में कुछ दिनों तक डोर-टू-डोर फूल बेचा। अंततः नगर निगम से कोठी कंपाउंड स्थित शिव मंदिर के बगल में जगह मांगी। उस दौर में दो-तीन फूलवाले बैठते थे, जो कि रोजाना फूल बेचकर घर आ जाते थे। पिता की पहल पर शुरू हुई फूलों की खेती अब कारोबार का रूप ले चुकी है।

दो एकड़ की बगिया में फूलों की खेती से साल 8 लाख की कमाई

विंध्य में फूल की खुशबू से महका बाजार

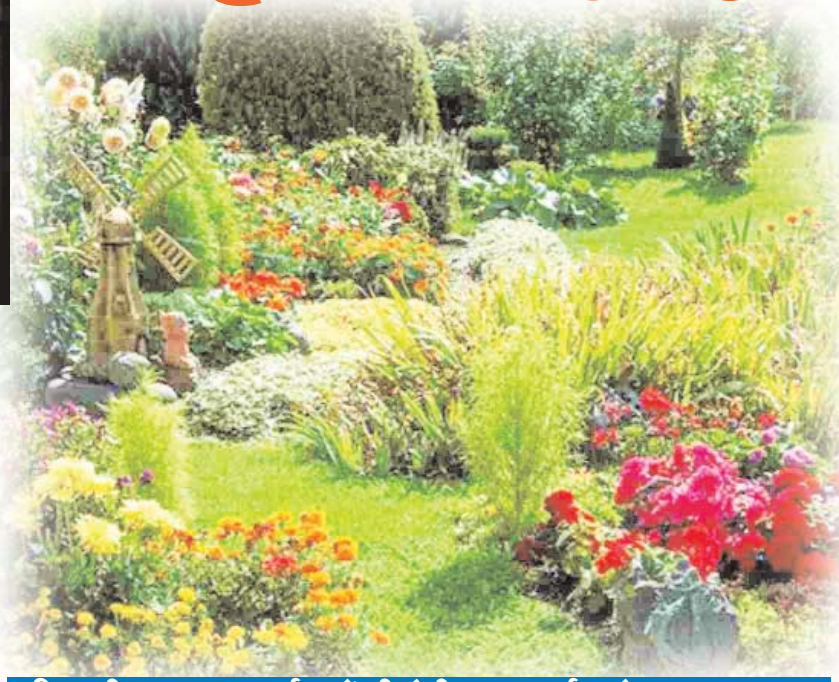

-पिता की पहल पर शुरू हुई फूलों की खेती अब बन गई कारोबार
-प्रगतिशील किसान ने कई दर्जन वैरायटी सीजनल फूलों की तैयार

सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं नर्सरी

अमित की मानें तो वे रोजाना सुबह 5 बजे फूलों के बगीचे में पहुंच जाते हैं। फूल तोड़कर 7 से 8 बजे तक बाजार पहुंच जाते हैं। बाजार में फूलों की सप्लाई देने के बाद फिर से अपने खेत में फूलों की देखभाल करने पहुंच जाते हैं। सालाना 2.5 से तीन लाख रुपए तक की आय फूलों की बिक्री से और फल, फूल व औषधीय पौधों समेत अन्य फसलों से चार से पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष आमदनी हो जाती है।

एक दर्जन से अधिक वैरायटी

प्रगतिशील किसान ने बताया कि उन्होंने कई दर्जन वैरायटी सीजनल फूलों की तैयार की है। उनके खेतों में सुंगधा, रजनीगंधा, जूही, चंपा, कृष्णकांता, बेला, गुलदाबड़ी, डहलिया, सुदर्शन, शिवकांता, अपराजिता, गेंदा, गेंदी, अष्टर और जरबेरा सहित आधा सैड़का फूलों की खेती करते हैं। शादी और पार्टी के सीजन में फूलों का भाव अच्छा मिल जाता है, बारिश के दिनों में कारोबार में नरमी रहती है।

इस तरह करें फूल की खेती

गेंदा को तीन बाई तीन, रजनीगंधा को दो बाई दो, सुदर्शन को दो बाई दो, गुलदाबड़ी को दो बाई दो और डेहलिया को तीन बाई तीन की क्यारी बनाकर लगाते हैं। पौधों के बीच में दूरी रखने से फूल को खुलकर फैलने का स्थान मिलता है। हम बागान में वर्मी कंपोज और गाय के गोबर से बनी खाद इस्तेमाल करते हैं। खेत में कभी आग नहीं लगाते।

ग्रीन हाउस में फूलों का उत्पादन

पुष्प कृषि उत्पादन के मामले में कट फोइलेज, पॉट प्लांट, कंद, खुले पुष्प, रुटेड़ कटिंग्स, सीड्स बल्बस और पत्तियां व सूखे फूल शामिल हैं। गुलनार और गारब्रेरास के फूलों का उत्पादन ग्रीन हाउस में किया जाता है। मेरीगोल्ड, लिलि, तारा, गेल्लारड्या, कंदाकार, गुलदाउदी और गुलाब को खुले खेत में उगाया जाता है। फूलों के उत्पादन में विलियम, स्वीट, डेहलिया, लुपिन, वेरबना, रैनन क्लाउज और कासमांस के फूलों की फसल उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त रात की रानी, मोगरा, मोतिया, साइप्रस चाइना और जूही जैसे छोटी ऊंचाई वाले पौधों को लगाकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं।

औषधीय पौधों की भी खेती

किसान ने बताया कि परदेश छोड़ पुस्तैनी जमीन में रोजगार के अन्य साधन भी बनाए है। हालांकि फूलों की बगिया पिता से विरासत में मिली है। पिता के सपनों को साकार करने और प्रकृति संरक्षण के उद्देश्य से फल, फूल और औषधीय पौधों की खेती करता हूं। जिससे सभी जगहों से थोड़ी-थोड़ी आय बनी रहे। बागान में चंदन, चीकू, नारियल, पपीता, आम, केला, नीबू, कटहल, सागौन सहित धान और गेहूं की खेती करता हूं।

37 साल से कर रहे जैविक खेती

किसान की मानें तो पिता डॉक्टर हैं, इसलिए रसायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। 37 साल से बागान में देशी खाद का उपयोग करते आ रहे हैं। हमारा मानना है कि फसल नष्ट हो जाए या उपज नहीं मिले, लेकिन खेती ऑर्गेनिक ही करते हैं। हम ज्यादा तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं, पुरानी पद्धति से ही खेती की जाती है। बारिश के बाद क्यारी बनाकर फूल की खेती करते हैं। दो बार हमारा बागान बाढ़ का शिकार हो चुका है। यहां से बीहर नदी निकलती है, जिससे हर पल डर बना रहता है। 2016 की बाढ़ में गुलाब का पूरा बाग नष्ट हो गया था।

बुरहानपुर में फूलों की खेती से फैली खुशियों की मुस्कान

संजय ने एक एकड़ में लिया 40 क्विंटल गेंदे का उत्पादन

मंडलेश्वर। फूलों का नाम आते ही खुशबू का अहसास होने लगता है, लेकिन जब इन्हीं फूलों की खेती की कमाई से जेब फूलने लगे तो चेहरे पर खुशियों की मुस्कान बरबस आ जाती है। फूलों की खेती करके इसे साबित किया है बुरहानपुर जिले के ग्राम चाकबारा के उन्नत किसान संजय महाजन ने। महाजन ने बताया कि केले की खेती तो वो लम्बे अर्से से कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। इस वर्ष तो भाव भी अच्छा मिल रहा है। फूलों की खेती 2001 से शुरू की थी। बीते दो दशकों से भी ज्यादा समय से गेंदे और सेवंती के फूलों की खेती कर

रहे हैं। सफेद सेवंती के अलावा गेंदे की पीली और ऑरेंज किस्म लगाते हैं। फूलों की खेती में लागत कम और लाभ अधिक मिलता है। गत वर्ष भी 17 एकड़ में गेंदा /सेवंती लगाया था। वैसे तो औसत उत्पादन 40 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाता है, लेकिन पिछले साल नवरात्रि के समय बारिश होने से फूलों की फसल को बहुत नुकसान हुआ। उत्पादन घटकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ रह गया। माल गीला होने से दाम भी कम मिला। संजय ने कहा कि फूलों की मांग ज्यादा होने पर 100 रुपए किलो तक बिक जाता है। वहीं उत्पादन अधिक होने पर कीमत जरूर कम मिलती है, लेकिन घाटा नहीं होता है। सामान्यत: 35 रुपए किलो और न्यूनतम 20 रुपए किलो का भाव तो मिल ही जाता है। लॉक डाउन के समय तो गेंदा 200 रुपए किलो तक बिका था। फूलों को प्राय: बुरहानपुर में ही बेचा जाता है, लेकिन कभी-कभी नागपुर और जलगांव भी कैरेट में फूल रखकर पिकअप वाहन से भेजे जाते हैं। वहां दाम अच्छे मिल जाते हैं। भाड़ा काटने के बाद भी अच्छा मुनाफा मिलने से चेहरे पर स्वत: खुशियों की मुस्कान छा जाती है।

राजस्व के साधनों में तब्दील होते वन बनाम वनाधिकार कानून

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को जारी नया फरमान, आदिवासियों और वनाश्रितों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय करने वाले तंत्र के चरित्र को एक बार फिर बेनकाब कर रहा है। वर्ष 1865, भारत में जब ब्रितानिया हुकूमत के द्वारा वनों और वन संसाधनों के दोहन के लिए वैधानिक बुनियाद रखी जा रही थी, तब भारत के लगभग 47 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र में जंगल थे, जिन पर आदिवासी और वनाश्रित समाज का सदियों से नैसर्गिक स्वामित्व रहा। लेकिन, ब्रितानिया हुकूमत के प्रथम वन कानून (1865) ने हमेशा के लिये वनों, वन संसाधनों और वनभूमि को राजस्व के साधनों में तब्दील कर दिया।

भारत के अनुमानतः 47 फीसदी वनक्षेत्र का भू-राजनैतिक स्वरुप तथा वनों से नैसर्गिक रूप से जुड़े आदिवासी समाज के अस्तित्व, अधिकारों और अर्थतंत्र को वर्ष 1865 के वन कानून के साथ ही सदा सर्वदा के लिये 'सशर्त रियायतों' में अपघटित कर दिया गया।

कालांतर में वर्ष 1927 के औपनिवेशिक भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत बाकायदा वन विकास निगम की स्थापना की गयी, जिसका वैधानिक मकसद वनों और वन संसाधनों का दोहन था/ और जो आज भी है। आज जब वन विभाग का वन विकास निगम ही वनों के दोहन के लिये वैधानिक रूप से जवाबदेह है, तब इस सवाल का भी स्पष्ट जवाब होना ही चाहिये कि – वर्ष 1927 से अब तक वन विकास निगम के माध्यम से कुल कितने पेड़ और जंगल काटे गये और उससे कितना राजस्व अर्जित किया गया?

वाकई में वन विभाग की संरचना और सोच, अब तक औपनिवेशिक ब्रितानिया हुकूमत के अधीन मालूम पड़ती है – जिनकी नजरों में जंगलों के सर्वकालीन संरक्षक, आदिवासी समाज की हैसियत आज भी एक अतिक्रमणकर्ता की है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन सेवा के अधिकारिओं को पढ़ाते हैं कि वनों का संरक्षक तो वन विभाग ही है – और इसीलिये वन विभाग की जागीर पर रहने वाला आदिवासी और वनाश्रित समाज अवैध अतिक्रमणकर्ता है।

वन अधिकारी और कर्मचारी यह भी पड़ते हैं कि वन विकास निगम द्वारा नियोजित और कार्यान्वित किये जाना वाला – राजस्व योग्य काष्ठीय पौधों का वनीकरण अथवा निर्वनीकरण 'पूर्णतः वैध' और इसका विरोध करने वाले 'अवैध अतिक्रमणकर्ता' हैं। जाहिर है, औपनिवेशिक वन अधिनियम (1927) पर आधारित पूर्वाग्रहपूर्ण शिक्षा प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के क्रियाकलाप और मानसिकता आदिवासी हितों के लिये होना संदिग्ध ही है।

वर्ष 2008 में वनाधिकार कानून (2006) के अधिसूचना के साथ ही भारतीय वन सेवा के (सेवानिवृत्त) अधिकारियों ने जब न्यायालय में वनाधिकार कानून की वैधता को चुनौती दी, तब उसके साथ ही यह सुनिश्चित हो गया कि वन विभाग अपने औपनिवेशिक चरित्र के चलते वनाधिकार कानून के मार्ग में स्थायी अवरोधक बना रहेगा। पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्रों में वन विभाग का संदिग्ध नजरिया और उसका जाहिरा परिणाम वनाधिकार कानून के वैधानिक और व्यवहारिक ढांचे को लगातार चुनौती दे रहा है।

वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में वनभूमि से तथाकथित अवैध अतिक्रमणकर्ताओं की बेदखली हेतु

(छदम पर्यावरणवादियों द्वारा) दाखिल याचिका इसकी ही बानगी है। इसके साथ-साथ वनाधिकार कानून (2006) के वैधानिक ढांचे को ही कुंद करने का नया प्रयास प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि विगत 2-3 बरस में वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की दर और गति विगत 15 वर्षों में सबसे कमजोर और धीमी रही है।

और अब, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को जारी नया फरमान, आदिवासियों और वनाश्रितों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय करने वाले तंत्र के चरित्र को एक बार फिर बेनकाब कर रहा है। इस फरमान के मुताबिक किसी भी (तथाकथित) विकास योजना के लिये स्थानीय आदिवासी और वनाश्रित समाज से मंजूरी लेने (या ना लेने) की जवाबदेही (अथवा औपचारिकता) अब राज्य सरकारों की है। वास्तव में यह फरमान, 'वेदांता बनाम डोंगरिया कंध आदिवासी पंचायत' प्रकरण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले का जाहिर उल्लंघन है जिसके मुताबिक (विकास योजनाओं के लिये किसी भी) निर्वनीकरण से पूर्व स्थानीय संबंधित आदिवासी समाज से वैधानिक अनुमति अनिवार्य है। 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करते हुये विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों नें भारत सरकार से अपील की है कि 28 जून 2022 को जारी आदेश वापस लिया जाना चाहिये ताकि आदिवासियों और वनाश्रित समाज के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। उम्मीद है भारत सरकार द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल की जायेगी।

गौरतलब है कि दिसंबर 2015 में स्वयं, भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि (विकास योजनाओं हेतु) निर्वनीकरण की प्रक्रिया से पूर्व स्थानीय आदिवासियों और वनाश्रित समाज से सहमति लेना आवश्यक है ताकि निर्णयों को ज्यादा वैधानिक, पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जा सके।

भारत के वन आच्छादन में शर्मनाक गिरावट: वन विभाग द्वारा संरक्षित जंगलों की वैध-अवैध कटाई और उससे अर्जित राजस्व तथा वनभूमि के अवैज्ञानिक विस्तार के चलते लाखों आदिवासियों को भूमिहीन बना देने की शर्मनाक कार्रवाई। जाहिर है, जिस ऐतिहासिक अन्याय के उपचार हेतु वनाधिकार कानून लागू किया गया वो भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण कानून 1980 के चलते न केवल बेमानी साबित हो रहे हैं, वरन वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में वैधानिक चुनौतियां खड़े कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि वनाधिकार कानून (2006) के वैधानिक प्रावधान और भावना के अनुरूप, स्वयं सरकारों द्वारा इसे प्रभावी तरीके से लागू करने का अभियान प्रारंभ करना चाहिये। अन्यथा वनाधिकार कानून, ऐतिहासिक न्याय का मार्ग कभी नहीं बन पायेगा।

(लेखक रमेश शर्मा – एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं)

पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण, वैज्ञानिकों के लिए बना चिंता का विषय, क्यों इसे कहा जा रहा है लाइलाज

एक संक्रामक, लाइलाज चर्म रोग ने राजस्थान और गुजरात में पशुओं पर मानों कहर बरपाया हुआ है। राज्य में लगभग तीन महीने में 1200 से अधिक गायों की इससे मौत हो चुकी है और 25000 मवेशी संक्रमित हैं। इस रोग का कोई सटीक उपचार न होने के कारण यह तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीमारी का प्रभाव मप्र के रतलाम में भी देखने को मिला है।

पशुओं में फैल रहे लंपी रोग से गो पालकों की चिंता बढ़ती जा रही है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि गांठदार चर्म रोग वायरस (एलएसडीवी) या लंपी रोग नामक यह संक्रामक रोग इस साल अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते भारत आया। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अफ्रीका में पैदा हुई यह बीमारी अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते भारत आयी थी। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गायों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अन्य रोग आक्रमण करते हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अफ्रीका में पैदा हुई यह बीमारी अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते भारत आयी थी। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गायों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अन्य रोग आक्रमण करते हैं।

इस विशेष बीमारी का कोई इलाज या टीका नहीं है और लक्षणों के अनुसार उपचार दिया जाता है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक लक्षण त्वचा पर चेचक, तेज बुखार और नाक बहना है। इस विशेष बीमारी का कोई इलाज या टीका नहीं है और लक्षणों के अनुसार उपचार दिया जाता है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक लक्षण त्वचा पर चेचक, तेज बुखार और नाक बहना है। इस वायरस के संक्रमण के बाद पशु को तेज बुखार आता है। बुखार आने के बाद उसकी शारीरिक क्षमताएं गिरने लगती हैं। कुछ दिनों बाद संक्रमित पशु के शरीर पर चकत्ते के निशान उभर आते हैं। इस वायरस के संक्रमण के बाद पशु को तेज बुखार आता है। बुखार आने के बाद उसकी शारीरिक क्षमताएं गिरने लगती हैं। कुछ दिनों बाद संक्रमित पशु के शरीर पर चकत्ते के निशान उभर आते हैं।

लंपी वायरस एक गाय से दूसरी गाय के सिर्फ संपर्क में आने पर ही फैल रहा है। लंपी त्वचा रोग एक संक्रामक बीमारी है, जो मच्छर, मक्खी, जूं इत्यादि के काटने या सीधा संपर्क में आने अथवा दूषित खाने या पानी से फैलती है। इससे पशुओं में तमाम लक्षणों के साथ उनकी मौत भी हो सकती है। लंपी वायरस एक गाय से दूसरी गाय के सिर्फ संपर्क में आने पर ही फैल रहा है। लंपी त्वचा रोग एक संक्रामक बीमारी है, जो मच्छर, मक्खी, जूं इत्यादि के काटने या सीधा संपर्क में आने अथवा दूषित खाने या पानी से फैलती है। इससे पशुओं में तमाम लक्षणों के साथ उनकी मौत भी हो सकती है।

यह बीमारी तेजी से मवेशियों में फैल रही है। इसे 'गांठदार त्वचा रोग वायरस' (एलएसडीवी) कहते हैं। दुनिया में मंकीपॉक्स के बाद अब यह दुलज्भ संक्रमण वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बना हुआ है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। वहीं रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीहिस्टामिनिक दवाएं दी जाती हैं। यह बीमारी तेजी से मवेशियों में फैल रही है। इसे 'गांठदार त्वचा रोग वायरस' (एलएसडीवी) कहते हैं। दुनिया में मंकीपॉक्स के बाद अब यह दुर्लभ संक्रमण वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बना हुआ है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। वहीं रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीहिस्टामिनिक दवाएं दी जाती हैं।

ब्रूसेलोसिस/ माल्टा ज्वरः पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली एक गंभीर बीमारी

ब्रूसेलोसिस एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु/ बैक्टीरिया के कारण होता है। जनवरो में ये मुख रूप से गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि को संक्रमित करता है। ब्रूसेलोसिस भारत में एक स्थानिक बीमारी है इससे डेयरी उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

ये बैक्टीरिया मनुष्यों को भी संक्रमित करते हैं। यह बीमारी मनुष्यों में अन्य नामों से भी जानी जाती है जैसे- माल्टा ज्वर या भूमध्य ज्वर। ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते है उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहा जाता है। अतः यह एक बहुत ही गंभीर जूनोटिक बीमारी है। यह रोग संक्रमित जानवरों या बैक्टीरिया से दूषित पशुओं के उत्पादों के संपर्क में आने से फैलता है। अतः इस बीमारी के बारे में जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है।

मनुष्यों में ब्रूसेलोसिस फैलने के मार्ग: 1. अधपका मांस खाने या अनपसचिरिज्ड / कच्चे डेयरी उत्पादों का उपभोग करना, संक्रमण का सबसे आम तरीका है। 2. ब्रूसेलोसिस बैक्टीरिया से दूषित/ संक्रमित वायु में सांस लेना, कसाईखाना और मांस-पैकिंग कर्मचारियों में आम है। 3. त्वचा के घाव या श्लेष्म झिल्ली के माध्यम से- जानवरों या पशु उत्सर्जन के साथ निकट संपर्क में रहने वाले लोग उदाहरण कसाईखाना कर्मचारी, पशु चिकित्सक, पशुपालक।

शुरुआती संकेत और लक्षण: बुखार, पसीना, अस्वस्थता, एनोरेक्सिया/ अरुचि, सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, संयुक्त, या पीठ, थकान।

कुछ लक्षण लंबे समय तक रह सकते हैं उदाहरणः बुखार का बारबार आना और जाना, गठिया, अत्यंत थकावट, डिप्रेशन, अंडकोष और वृषण क्षेत्र की सूजन, हृदय की सूजन (एन्डोकार्टिटिस)

अनीता तिवारी, बालेश्वरी दीक्षित, योगेश चतुर, मनोज अहिरवार
पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा

तंत्रिका संबंधी लक्षण (सभी मामलों में 5प्रतिशत तक), यकृत और / या तिल्ली की सूजन।

संक्रमण रोकने का सबसे अच्छा तरीका: 1. अधपका/ अंडरकुवड मांस का उपभोग न करें।

2. अधपका/ अनपस्च्युरेटेड डेयरी उत्पादों (दूध, पनीर, आइसक्रीम) का उपभोग न करें।

3. जो लोग पशु या पशु उत्सर्जन के साथ काम करते हैं (जैसे कि शिकारी, पशु चिकित्सक, पशुपालक), उनको रबड़ के दस्ताने, काले चश्मे, गाउन या एप्रॉन उपयोग करके स्वयं को बचाया जाना चाहिए।

4. मादा पशुओं में प्रसव के समय कर्मचारी को दस्ताने या कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए।

5. यह रोग पशु से इंसान मे फैलता है इसलिए पशुओ/ गाय- बछड़ो मे ब्रूसेलोसिस का सही समय पर टीकाकरण करवाए।

6. बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जानवरों को स्वस्थ जानवरों से अलग किया जाना चाहिए।

7. पशुओ/ गाय- बछड़ों मे टीकाकरण- बीमारी को फैलने से रोकने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ब्रूसेलोसिस के उपलब्ध टीके गोजातीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रमों में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं और दशकों से दुनिया भर में सफलतापूर्वक उपयोग किए जा रहे हैं। स्ट्रेन 19 और आरबी51 स्वीकृत बी. एबॉर्टस वैक्सीन स्ट्रेन हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर मवेशियों को संक्रमण और गर्भपात से बचाने के लिए किया जाता है।

ब्रूसेलोसिस का निदानः ब्रूसेलोसिस आमतौर पर फ्लू की तरह होता है जिसके लक्षण अस्पष्ट है। परन्तु संशय की स्थिति में, या ब्रूसेलोसिस से मिलते जुलते लक्षण प्रकट होने की स्तिथि में रोगी को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमेशा प्रमाणित डॉक्टर द्वारा निर्धारित उपचार लेना चाहिए। ब्रूसेलोसिस का निदान करने के लिए टेस्ट में रक्त संस्कृति, मूत्र संस्कृति, अस्थि मज्जा संस्कृति, सेरेब्रोस्पाइनल तरल परीक्षण और एंटीबॉडी के परीक्षण शामिल हैं। ब्रूसेलोसिस के लक्षणों के संकेतों के लिए यह एक सप्ताह से दो महीने तक कहीं भी ले सकता है। इसका इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है, जिसमें रिफैम्पिन और डॉक्सीसाइक्लिन शामिल हैं।

भोपाल। अगर औषधीय फसलों की बोवनी सही समय पर की जाए और सही सिंचाई और कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाए, तो फसल से काफी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। कुछ औषधीय पौधे, जिनकी बोवनी अगस्त में आसानी से की जा सकती है। इससे उत्पादक सही समय पर गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त कर सकते हैं। खेती-किसानी में रोजाना नए-नए प्रयोग हो रहे हैं। परंपरागत खेती से इतर लोग मुनाफे वाली फसलों की तरफ लोग तेजी से रूख कर रहे हैं। गौरतलब है कि किसानों के बीच औषधीय फसलों की खेती भी बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रही है। सरकार द्वारा भी बड़े स्तर पर इन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि, ज्यादातर किसानों को औषधीय फसलों की खेती को लेकर जानकारी नहीं होती है। ऐसे में बिना जानकारी इन फसलों की खेती से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर औषधीय फसलों की बोवनी सही समय पर की जाए तो हम अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। 'जागत गांव हमार' अपने इस अंक में किसानों को बता रहा है कि अगस्त में किन औषधीय फसलों की बोवनी की जा सकती है।

अगस्त-सितंबर का महीना बोवनी के लिए माना गया सबसे उपयुक्त

कलिहारी की खेती

अगस्त का महीना कलिहारी की बोवनी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसके लिए दोमट मिट्टी की जरूरत रहती है। मानसून में इसकी खेती करने से फसल को सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कलिहारी की रोपाई करनी है, तो करीब 10 क्विंटल कंदों यानी कलिहारी के फल की जरूरत होती है। खाद के तौर पर गोबर का उपयोग कर इस फसल को अच्छा पोषण दिया जा सकता है।

खेती कैसे करें

इसकी खेती जुलाई और अगस्त महीने में उत्तम होती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पौधे को 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाए। कलिहारी खेती के लिए पिछली फसल की गांठों को या फिर तैयार बीजों से पनीरी तैयार करके रोपाई की जाती है।

बीज की मात्रा

यदि आप एक एकड़ में कलिहारी की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए 10 से 12 क्विंटल गांठों की जरूरत पड़ती है। रोपाई से पहले गांठों को अच्छी तरह से उपचारित कर लेना चाहिए।

खाद एवं उर्वरक

अच्छी पैदावार के लिए प्रति एकड़ नाइट्रोजन 48 किलो ग्राम, फास्फोरस 20 किलो ग्राम और पोटाश 28 किलो डालना चाहिए। शुरूआत में नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा डालना चाहिए। इसके बाद यूरिया की दो खुराक 30 और 60 दिन के अंतराल पर डालें।

सिंचाई

इसकी खेती में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फल पकने के समय दो बार सिंचाई जरूर करना चाहिए. वहीं कटाई से पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।

कटाई

इसकी खेती 170 से 180 दिनों की होती है. जब इसके फल हल्के हरे और गहरे रंग के हो जाए तब तुड़ाई करना चाहिए। यदि आप बीज प्राप्त करना चाहते हैं तो फल को अच्छी तरह से पकने के बाद तोड़ना चाहिए।

औषधीय पौधों की खेती से कई गुना लाभ

सनाय की खेती

अगस्त के महीने में बोई जानी वाली फसलों में से सनाय भी एक फसल है। यह फसल भी अपने औषधीय गुणों की वजह से किसानों के बीच लोकप्रिय है। इसकी बोवनी लाइनों और डिब्लर विधि से होती है। इस विधि में 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ती है।

ज्यादा मुनाफा

इन दोनों पौधों की पत्तियों का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के खिलाफ किया जाता है। इसके अलावा इनकी छाल से लेकर पत्ते तक का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में होता है। ऐसे में इन्हें आप दवा निर्माता कंपनियों को बेचकर ठीक-ठाक मुनाफा कमा सकते हैं।

सनाय

सनाय एक औषधीय पौधा है जो एक बार लगा देने के उपरांत 4-5 वर्ष तक उपज देता है। इसका पौधा 4 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन करने की क्षमता रखता है। एक बार लगा देने के बाद इस फसल के पौधों को न तो कोई जानवर एवं पशु पक्षियों से नुकसान होता है और ना ही कीटो का प्रकोप बहुत होता है। दलहनी पौधा होने के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। इसकी पत्तियों, फलियों को विदेशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। सोनामुखी की खेती भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात में विशेष रूप से होता है।

उन्नत खेती

सोनामुखी या सनाय बहुवर्षीय कांटे रहित झाड़ीनुमा, औषधीय पौधा है, जो लेग्यूमिनोसी (दलहनी) कुल के अंतर्गत आता है। पूर्णतया बंजर भूमि में उगाए जा सकने वाले इस पौधे के लिए ज्यादा पानी एवं खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार भारत के बंजर भूमि वाले भागों में सोनामुखी की खेती करके पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है।

सनाय की किस्में

एएचएफटी: इस किस्म को गुजरात में बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है। इसको विशेष रूप से पत्तियों के लिए उगाया जाता है।

सोना: इस किस्म को उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में उगाने हेतु संस्तुत किया गया है। पत्तियों में सोनासाइड 3.51 फीसदी तक पाया जाता है।

सिंचाई: वर्षा ऋतु में यदि काफी लंबे समय तक वर्षा ना हो तो आवश्यकतानुसार उपलब्ध होने पर सर्दियों में 30 दिन और गर्मियों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण: फसल की अवस्था में यदि खेत में खरपतवार ज्यादा उग जाए तो आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। वैसे इसकी फसल के 30 दिन की हो जाने के बाद निराई-गुड़ाई की आमतौर पर बहुत कम आवश्यकता होती है।

रोग नियंत्रण: सनाय के पौधों पर कोई विशेष कीट एवं बीमारी का प्रकोप नहीं होता है परंतु कभी-कभी पत्ती खाने वाली सुंडी, सफेद मक्खी, फली बेधक आदि कीट तथा आर्द्र विगलन (डेम्पिंग ऑफ) नामक रोग का प्रकोप हो जाता है। अतः इसके नियंत्रण के लिए किसी उपयुक्त कीटनाशी एवं फफूंदनाशी रसायन का प्रयोग करना चाहिए।

फसल कटाई: सनाय की बिजाई के लगभग 100 से 120 दिनों के उपरांत इसकी पत्तियां काटने लायक हो जाती है। पौधों की कटाई तेज धारदार वाले हंसिये द्वारा जमीन से 3 इंच ऊपर से करनी चाहिए ताकि उसमें आसानी से दोबारा पत्ते आ जाए। प्रथम कटाई से 60 से 75 दिन के अंतराल पर इस फसल की अगली कटाई करनी चाहिए।

उपज

बारानी क्षेत्रों में इस फसल से लगभग 400 से 600 किग्रा सूखी पत्तियों का उत्पादन होता है। बीज का उत्पादन बारानी व सिंचित दशा में क्रमशः 4 क्विंटल व 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है।

उपयुक्त जलवायु

यह पछेती खरीफ फसल है। यह उष्णकटिबंधी और समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। अश्वगंधा को शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। बारिश के महीने के अंतिम दिनों में इसे बोया जाता है। फसल के विकास के लिए शुष्क मौसम अच्छा रहताहै। जिन स्थान में वर्षा 660-750 मिमी की होती है वे स्थान फसल के विकास के लिए उपयुक्त होते है। वार्षिक वर्षा 600 से 750 मिलीलीटर में अश्वगंधा की वृद्धि अच्छी से होती है।

कैसी हो जमीन: अच्छे जल निकास वाली बलुई, दोमट मिट्टी या हल्की लाल मृदा, जिसका पीएच मान 7.5 से 8 हो, प्रयुक्त मानी जाती है। कम उपजाऊ भूमि में भी अश्वगंधा की खेती से संतोषजनक उपज ली जा सकती है।

खेत की तैयारी: डिस्क हैरो या देशी हल से दो या तीन बार अच्छी तरह जुताई करके सुहागा लगाकर खेत को समतल बना लें। खेत में खरपतवार ढेले नहीं होने चाहिए।

बोवनी की विधि: सीधे बीज से अश्वगंधा की बिजाई अधिकतर छिड़काव द्वारा की जाती है। बीजों को बोने से पहले नीम के पत्तों के काढ़े से उपचारित करें। बीज को डायथेन एम-45 से उपचारित करते हैं। एक किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए 3 ग्राम डायथेन एम का प्रयोग किया जाता है। जिससे फफूंदी आदि से हानि न होने पाये। अश्वगंधा अच्छी फसल के लिये कतार से कतार का फासला 20 से 25 सेमी तथा पौधे से पौधे का 4-6 से.मी. होना चाहिए। बीज 2-3 सेमी से अधिक गहरा नहीं होना चाहिये। इससे एक एकड़ में लगभग 3-4 लाख पौधे लग सकते हैं। बोवनी के 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। अश्वगंधा को नर्सरी में पौधे तैयार करके भी खेत में लगाया जा सकते हैं तथा 6-7 सप्ताह बाद पौधों को नर्सरी से खेत में लगा दिया जाता है। जिससे लाइन से लाइन का फासला 20-25 सेमी तथा पौधे से पौधे का फासला 4-6 सेमी रखना चाहिये। एक एकड़ नर्सरी के लिये 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल काफी होता है। नर्सरी में क्यारियां 1.5 मीटर चौड़ी तथा लंबाई सुविधानुसार रखकर बनाएं। नर्सरी जमीन से 15-20 सेमी उठी हुई हो तथा अच्छे जमाव के लिए नर्सरी में नमी बनाएं रखें।

बीज की मात्रा: नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेअर 5 किलोग्राम व छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेअर 10 से 15 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। बोवनी के लिए जुलाई से सितंबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है।

बोवनी का समय: अश्वगंधा की बुवाई के समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिये। जब एक-दो बार वर्षा हो जाती है तथा खेत की जमीन अच्छी तरह से संतृप्त हो जाये तभी बोवनी करनी चाहिए। अगस्त का महीना अश्वगंधा की बोवनी के लिए उत्तम है। सिंचित अवस्था में उसकी बिजाई सितम्बर के महीने में भी कर सकते हैं।

किस्म: डब्लूएस-20 (जवाहर), डब्लू एस आर, जवाहर अश्वगंधा-20, जवाहर अश्वगंधा-134 किस्में मुख्य हैं। सीमेप ने भी पोषिता किस्म विकसित की है।

खाद व सिंचाई: अच्छी फसल लेने के लिए खेत की तैयारी के समय 8-10 टन गोबर की अच्छी गली-सड़ी खाद मिला दें। अश्वगंधा की फसल को पानी में अधिक आवश्यकता नहीं होती व वर्षा समय पर न हो तो अच्छी फसल लेने के लिए 2-3 सिंचाई करें।

फसल सुरक्षा: अश्वगंधा पर रोग व कीटों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कभी-कभी माहू कीट तथा पूर्णझुलसा रोग से फसल प्रभावित होती है। ऐसी परिस्थिति में मोनोक्रोटोफास का डायथेन एम- 45, तीन ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बोआई के 30 दिन के अंदर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के अंदर दोबारा छिड़काव करें।

उत्पादन: फसल बोवनी के 150 से 170 दिन में तैयार हो जाती है। अश्वगंधा की फसल से प्रति हेक्टेअर 3 से 4 कुंतल जड़ व 50 किग्रा बीज प्राप्त होता है। इस फसल में लागत से तीन गुना अधिक लाभ होता है। पत्तियों का सूखना फलों का लाल होना फसल की परिपक्वता का प्रमाण है। परिपक्व पौधे को उखाड़कर जड़ों को गुच्छे से दो सेमी ऊपर से काट लें फिर इन्हें सुखाएं।

पशुपालन योजनाओं के संचालन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल

मंत्री ने कहा- गौ-मूत्र, गोबर, गौ-उत्पाद आय के बने साधन

मप्र को हर माह 15 हजार किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का मिला लक्ष्य

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि मध्यप्रदेश किसान क्रेडिट-कार्ड, टेगिंग, टीकाकरण, अधो-संरचना विकास आदि कार्यों में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे चल रहा है। इन सफलताओं का ही परिणाम है कि आज प्रदेश को किसान क्रेडिट-कार्ड में 15 हजार कार्ड प्रतिमाह का नया लक्ष्य मिला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह लक्ष्य भी विभाग इसी गति से शत-प्रतिशत हासिल कर लेगा। मंत्री ने यह बात संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी में लिफ्ट सुविधा का लोकार्पण करते हुए कही। मंत्री ने कहा कि अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया और उनके बीच विभाग के लिए नित नए आयाम स्थापित करने की जिजिविषा के साथ विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों की मेहनत और लगन का परिणाम है कि प्रदेश आज देश में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर है। प्रदेश में कुछ वर्ष पहले गाय से एक लीटर दूध मिलता था, वह अब बढ़कर 10 लीटर तक हो गया है। गौ-मूत्र, गोबर, गौ-उत्पाद अब आय के साधन बन चुके हैं। इस कार्य संस्कृति को बनाए रखें।

पशु-सखी की ली जानकारी

मंत्री पटेल, अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी कंसोटिया, वेटनरी काउंसिल ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष डॉ. उमेश शर्मा और संचालक डॉ. आरके मेहिया ने संचालनालय परिसर में आम, जामुन, चीकू आदि के पौधे रोपे। मंत्री ने राष्ट्रीय योजना में प्रशिक्षित पशु-सखी ए-हेल्प से भी प्रशिक्षण और गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। पटेल ने संचालनालय में प्रशिक्षणरत अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों से भी चर्चा की।

एक लाख का बकरा 5 लाख में बिका

नीमच के कन्हैया लाल ने बताया कि पशुपालन, मुर्गीपालन आदि के लिए मिल रहा प्रशिक्षण बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। प्रशिक्षण के बाद उनके द्वारा पोषित बकरा एक लाख रुपए में बिका, जिसे खरीददार ने पूना में 5 लाख रुपए में बेच दिया। प्रशिक्षण से छोटे पशुपालकों की आय में जो बढ़ोत्तरी हो रही है, उसके लिए हम शासन के शुक्रगुजार हैं। उप संचालक डॉ. प्रियनाथ पाठक कार्यक्रम का संचालन किया। संयुक्त संचालक डॉ. पीएस पटेल ने आभार माना।

-लोगों तक पहुंचाने चलित सांची पार्लर का लोकार्पण

सांची के उत्पाद भी अपरोक्ष रूप से किसानों की देन

पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने हाल ही में भोपाल दुग्ध संघ परिसर में सांची के नए उत्पाद- गाय का घी, बृज पेड़ा और बेसन के लड्डू लांच किए। मंत्री ने सांची के उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए चलित सांची पार्लर का लोकार्पण भी किया। इसका फायदा उन क्षेत्रों को भी मिलेगा जहां सांची पार्लर नहीं हैं। अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी जेएन कंसोटिया, प्रबंध संचालक स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तरूण राठी सहित सांची की नव-नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार भी उपस्थित थीं। मंत्री ने कहा कि सांची के उत्पाद- दूध, दही, मट्ठा, घी, श्रीखंड, सुगंधित दूध आदि की प्रदेश में काफी मांग है। राखी के त्यौहार की मिठास बढ़ाने के लिए आज भोपाल दुग्ध संघ का गाय का घी, बृज पेड़ा और ग्वालियर दुग्ध संघ के बेसन के लड्डू शुरू किए गए हैं। उन्होंने एवरेस्ट फतह करने वाली मध्यप्रदेश की बेटी मेघा परमार को प्रदेश का गौरव बढ़ाने और सांची ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बधाई दी। सांची के उत्पाद भी अपरोक्ष रूप से किसानों की ही देन है। अपर मुख्य सचिव कंसोटिया ने कहा कि सांची देश का माना हुआ ब्रांड है। मेघा परमार के जुड़ने से इसका और अधिक विकास होगा। उत्पादों की लोकप्रियता देखते हुए प्रदेश के सभी दुग्ध संघ नए उत्पाद ला रहे हैं। प्रबंध संचालक राठी ने कहा कि प्रदेश में ऐसे 100 सांची पार्लर संचालित किए जाएंगे। सांची पार्लर्स से गत वर्ष 37 मीट्रिक टन मिठाई का विक्रय हुआ। इस वर्ष 50 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीईओ तिवारी ने बताया कि सांची के उत्पाद रक्षा विभाग, स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं। एफसीसीआई के हाल में किए गए ऑडिट में सांची उत्पाद को 100 में 96 अंक प्राप्त हुए हैं। मेघा परमार ने कहा कि वह खुद किसान परिवार से आती हैं। सांची से जुड़े उनके पिता की मुख्य आमदनी डेयरी व्यवसाय से ही होती थी। इस ऊंचाई तक पहुंचने में सांची से हुई आमदनी की मुख्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि बचपन से पिता के साथ सांची के टेंकर, दूध संकलन की प्रक्रिया आदि देखती आ रही थी, आज ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बहुत सौभाग्य महसूस कर रही हूं।

निवेश संवर्धन समिति: कृषि विविधीकरण की दो परियोजना मंजूरी

-आईटीसी और ग्रीन एंड ग्रेस कंपनी किसानों को करेगी प्रेरित

गेहूं, धान की जगह लाभकारी फसलों को करेंगे प्रोत्साहित

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में किसानों को गेहूं, धान सहित अन्य परंपरागत फसलों की जगह लाभकारी फसलों की खेती करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। इस दिशा में काम करने वाली कंपनियों की हर संभव सहायता की जाएगी। साथ ही किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कंपनियां किसानों से जिस उत्पाद की खेती कराएगी, उसे खरीदने की व्यवस्था भी करनी होगी। आइटीसी और ग्रीन एंड ग्रेस कंपनी किसानों को औषधीय और जैविक खेती के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई निवेश संवर्धन समिति की बैठक में कृषि विविधीकरण की दो परियोजना को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पायलट आधार पर प्राकृतिक कृषि के लिए क्षेत्र चयनित कर कार्य प्रारंभ किया गया है। किसानों के आर्थिक हित को देखते हुए मध्य प्रदेश फसल विविधिकरण योजना तीन साल के लिए लागू की गई है। फसल विविधिकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से आगे बढ़ रहा है। गेहूं और धान के स्थान पर प्राकृतिक कृषि में अन्य अनाज की फसलें लिए जाने की पहल की गई है। सोयाबीन का रकबा कम न हो क्योंकि यह भी राज्य की आवश्यकता है।

किसानों का कर रहे प्रोत्साहित

बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी ने बताया कि फसल विविधिकरण में कृषकों को उद्योगों के साथ कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दौरान आईटीसी के सुधांशु ने बताया कि उन्होंने सुगंधित औषधीय पौधों के उत्पादन का काम सीहोर में प्रारंभ किया है। वैज्ञानिक शोध के आधार पर तुलसी की अनेक प्रजातियों में से अनुकूल प्रजाति का चयन किया गया है।

पायलट प्रोजेक्ट जुड़े किसान

पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए किसान प्रेरित हुए हैं। वहीं, ग्रीन एंड ग्रेस कंपनी प्रतीक शर्मा ने बताया कि वे नर्मदापुरम में पिछले सात साल से काम कर रहे हैं। इससे लागत में बीस प्रतिशत की कमी और उत्पादन विक्रय में 25 से 30 प्रतिशत अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। बैठक में दोनों कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

-लोक सेवा गारंटी कानून में शामिल सहकारिता की सेवा

किसानों के ऋण आवेदन पर 30 दिनों में करना होगा निर्णय

-आवेदन का निराकरण करने की अवधि भी निर्धारित की

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों को अब अधिक इंतजार नहीं करना होगा। उनके आवेदन पर समिति को 30 दिन में निर्णय करना होगा। इसी तरह कोई किसान समिति का सदस्य बनना चाहता है तो उसके आवेदन पर भी निर्णय 30 दिन में ही लेना होगा। इसके लिए सरकार ने सहकारिता विभाग की किसानों से जुड़ी इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण लेते हैं। इसमें 75 प्रतिशत राशि नकद और शेष 25 प्रतिशत ऋण सामग्री के तौर पर दिया जाता है। कृषि ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। सहकारी बैंकों को सरकार ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए वार्षिक 800 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। सभी किसानों को इस सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता विभाग की इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत समिति के सदस्य कृषक के ऋण संबंधी आवेदन का निराकरण प्रबंधक यदि 30 दिनों में नहीं करता है तो किसान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास अपील कर सकेगा। इस स्तर पर भी तीस दिन में आवेदन का निराकरण करना होगा। इसी तरह कोई किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य बनना चाहता है तो उसके आवेदन पर तीस दिन में निर्णय करना होगा। यदि कोई समिति अपना पंजीयन निरस्त कराना चाहती है तो उस पर निर्णय लेने की अवधि तय कर दी गई है। तीस दिन में निर्णय लेकर संबंधित को सूचित किया जाएगा।

-डेयरी क्षेत्र से जुड़े पशुपालकों के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार

गाय-भैंस की देशी नस्लों के संरक्षण पर मिलेगा सम्मान

भोपाल। जागत गांव हमार

डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी खबर है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है। वैज्ञानिक तरीके से दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के तहत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को 100 प्रतिशत एआई कवरेज लेने के लिए प्रेरित करना। सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को विकसित होने और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करना।

ये करें आवदेन- 50 नस्लों के मवेशियों और भैंसों की 17 नस्लों में से किसी भी मान्यता प्राप्त देशी नस्ल को बनाए रखने वाले किसान पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशुधन विकास बोर्ड/राज्य/दूध संघों/गैर सरकारी संगठनों और अन्य निजी संगठनों के एआई तकनीशियन जिन्होंने कम से कम 90 दिनों के लिए एआई प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। एक सहकारी समिति / दुग्ध उत्पादक कंपनी, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) जो ग्रामीण स्तर पर स्थापित डेयरी गतिविधियों में लगी हुई है और सहकारी अधिनियम / कंपनी अधिनियम के तहत प्रतिदिन कम से कम 100 लीटर दूध इकट्ठा करती है और कम से कम 50 किसान है।

इस तरह होगा चयन

अधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जांच क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी अन्य एजेंसी द्वारा की जाएगी। एजेंसी डीएएचडी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन/स्कोर कार्ड के अनुसार आवेदनों को स्कोर करेगी और डीएएचडी द्वारा गठित पुरस्कार स्क्रीनिंग समिति को प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ 20 आवेदनों की सिफारिश करेगी। सभी शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों का फील्ड विजिट/सत्यापन एनडीडीबी/डीएएचडी द्वारा पहचानी गई किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।

अवार्ड स्क्रीनिंग कमेटी करेगी सिफारिश

अवार्ड स्क्रीनिंग कमेटी, डीएएचडी सर्वश्रेष्ठ आवेदकों को छांटेगी और एनएसी को इसकी सिफारिश करेगी। समिति, यदि आवश्यक हो, केंद्र/राज्य/एनडीडीबी अधिकारियों को शामिल करके या किसी बाहरी एजेंसियों को किराए पर लेकर भौतिक सत्यापन/लाइव वीडियो फुटेज मांग सकती है। समिति अपनी संतुष्टि में स्क्रीनिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रमाण मांग सकती है। इस प्रयोजन के लिए आरजीएम योजना के बजट प्रावधान से व्यय की पूर्ति की जाएगी।

समिति तय करेगी मानदंड

समिति स्क्रीनिंग के लिए कार्यप्रणाली और मानदंड तय करेगी। पुरस्कार विजेताओं के नामों की आधिकारिक घोषणा होने तक समिति पुरस्कारों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर गोपनीयता बनाए रखेगी। स्क्रीनिंग कमेटी आवेदन को अस्वीकार करने, सिफारिश किए जाने वाले पुरस्कार विजेताओं की संख्या पर निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखेगी। स्क्रीनिंग कमेटी के गैर-सरकारी सदस्य सामान्य वित्त नियमों के अनुसार टीए/डीए के हकदार होंगे।

अक्टूबर में घोषणा, नवंबर में पुरस्कार

प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा 31 अक्टूबर 2022 (सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन) पर की जाएगी। पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2022 को पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा तय किए गए स्थान पर आयोजित किया जाएगा।

राजस्व मंत्री बोले-आपदा में जनता के साथ खड़ी है राज्य सरकार

बाढ़, अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में 25 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित

भोपाल। जागत गांव हमार

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली से मौत, पशुहानि, जनहानि एवं मकान के क्षतिग्रस्त होने के मामलों में अब तक लगभग 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा प्रभावितों को वितरित की गई है। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में अतिवृष्टि के बाद जो नुकसान हुआ है, वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रभावितों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व विभाग के साथ स्थानीय अमला सर्वे कर रहा है। मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश के 29 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने, 12 जिलों में बाढ़-अतिवृष्टि, 30 जिलों में पशुहानि के मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 40 जिलों के 397 ग्राम में बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षति की जानकारी मिली है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान 4-6 के अनुसार प्रभावितों को लगभग 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि अब तक वितरित की गई है। राजपूत ने कहा कि अतिवृष्टि से जिन क्षेत्रों में किसानों को नुकसान हुआ है, वहां की सर्वे रिपोर्ट जल्द तैयार कर आपदा राहत कोष से तात्कालिक सहायता राशि बांटी जाएगी।

बारिश की अच्छी स्थिति

मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अभी बारिश की स्थिति अच्छी है। रीवा और शहडोल संभाग में कम बारिश की जानकारी प्राप्त हुई है। आने वाले समय में पर्याप्त बारिश की उम्मीद जताई जा रही है।

रतलाम में 38 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण

अमित निगम, रतलाम।

जिले में लंपी वायरस के लक्षण पशुओं में नजर आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले के ग्राम सेमलिया और बरबोदना में पशुओं में बीमारी के लक्षण नजर आए हैं। मामला उजागर होने के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने गांवों में जाकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में 38 पशुओं में इसके लक्षण नजर आए हैं। ऐसे में उक्त पशुओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए है। अब जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। रतलाम के साथ ही जिले के सीमावर्ती राजस्थान राज्य की सीमा बांसवाड़ा में बीमारी से 16 पशु ग्रसित पाए गए हैं। रतलाम में बीमारी की रोकथाम के लिए टीका द्रव्य शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था गुजरात की कंपनी से चर्चा करके की जा रही है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पशु चिकित्सा सेवा विभाग के डॉक्टर्स के दल बनाकर उन्हें जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. आरके शर्मा ने बताया कि वायरस से गोवंश के बचाव के लिए विकासखंड स्तरीय आरआरटी टीमों का गठन किया गया है। इनमें डॉक्टर्स के साथ-साथ वीएफओ तथा अन्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिनके द्वारा स्थलों पर पहुंचकर पशुओं का उपचार किया जा रहा है।

गौ-शाला में 42 प्रकार की औषधि का भी किया जा रहा निर्माण

कामधेनु गौ-शाला में 200 गाय, 10 से 24 तक दे रहीं दूध

-गौ-संवर्धन बोर्ड अध्यक्ष ने पशु चिकित्सा शिविर का लिया जायजा

-अखिलेश्वरानंद ने की गौवंश के बेहतर स्वास्थ्य-स्वच्छता की प्रशंसा

भोपाल। जागत गांव हमार

गौ-संवर्धन बोर्ड की कार्यपरिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि की उपस्थिति में भोपाल में शारदा विहार स्थित कामधेनु गौ-शाला एवं गौ-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र में गायों को गलघोंटू, एक टंगिया आदि बीमारियों का टीकाकरण करने के साथ ही बछड़े-बछड़ों को कृमि-नाशक दवाइयां दी गईं। स्वामी गिरि, वेटनरी काउंसिल ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष डॉ. उमेश शर्मा,

संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉ. आरके मेहिया ने उपचार के लिए गौ-शाला को औषधियां भी भेंट की। गिरि ने गौ-शाला में 200 से अधिक गिर नस्ल की गायों के रख-रखाव, स्वास्थ्य और स्वच्छता की प्रशंसा की। गौ-शाला दो भागों में विभक्त है। एक खंड में दुधारू गाय हैं। अधिकांश गाय 10 से 24 लीटर तक दूध दे रही हैं। दूसरे खंड में बेसहारा और बीमार गायों को प्रश्रय दिया जाता है। इन गायों का गौ-मूत्र और गोबर भी गौ-काष्ठ, फिनायल आदि बनाने में उपयोग होता है। गौ-शाला के अनुसंधान केन्द्र में 42 प्रकार की औषधि का भी निर्माण किया जाता है। तुलसी और आंवले के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली एवं मेपकास्ट के सौजन्य से गौ-शाला में बायो-सीएनजी प्लांट भी लगाया गया है। गौ-शाला संचालक, विष्णु पाटीदार, अजय शिवहरे और प्रकाश मंडलोई ने गौ-शाला की गतिविधियों से स्वामी को अवगत कराया।

पशु पालकों को किया जा रहा जागरुक

संयुक्त संचालक डॉ. बीएस शर्मा के नेतृत्व में डॉ. नीना त्रिपाठी, डॉ. नीता रावत, डॉ. शोभना कौशल, डॉ. पूजा गौर, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी बीएस कुशवाह, सीपीएस ठाकुर, एमएस मेहता, सुनीता खरते, रमेश सोनीने और डॉ. स्नेहलता की टीम द्वारा लगातार शिविर लगाकर पशुओं का उपचार, टीकाकरण करने के साथ पशु-पालकों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पशु चिकित्सा सेवा माता महामारी इकाई द्वारा प्रदेश की गौ-शालाओं में गौवंश को निरोग रखने के लिए माता महामारी जन-जागरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष होने वाला यह शिविरों का सिलसिला अप्रैल माह से जारी है।

-यूरोपीय देशों की विंड ब्रेक तकनीक:प्रदेश का पहला ऐसा पार्क बनेगा 'एकांत' जहां बढ़ेगा ऑक्सीजन इंडेक्स और दूर होगा वॉटर पॉल्यूशन

बांस और खस के छह हजार पौधों की बन रही दीवार...

भोपाल। जागत गांव हमार

कभी सीपीए के अधीन रहा एकांत पार्क यहां बह रहे तीन नालों की वजह से प्रदूषित हो गया है। इन नालों से शहर की विभिन्न कॉलोनियों का सीवेज बहकर शाहपुरा तालाब तक पहुंचता है। यहां वॉक पर आने वाले वीआईपी को हमेशा बदबू का सामना करना पड़ता है। अब पर्यावरण वन मंडल ने इस पार्क को बदबू रहित बनाने, यहां की मिट्टी और पानी को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया है।

पर्यावरण वन मंडल के अधिकारी विंड और वॉटर ब्रेक तकनीक का उपयोग करके यहां दो ऐसी प्रजाति के पौधे लगा रहे हैं, जिससे मिट्टी व नालों में बहने वाला पानी हैवी मेटल मुक्त होगा। साथ ही पार्क का ऑक्सीजन इंडेक्स बढ़ेगा। इन नालों के किनारे खस और बांस के 6 हजार पौधे लगाए जा रहे हैं।

बदबू से जागे जिम्मेदार- पर्यावरण वन मंडल के अधिकारियों का कहना है कि जब उन्हें पार्कों की सेहत सुधारने की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा बुरी स्थिति एकांत पार्क की है। यह वह पार्क है, जहां पर रोज करीब डेढ़ हजार वीआईपी वॉक करने पहुंचते हैं। जब वन विभाग के अधिकारियों ने यहां का दौरा किया तो पार्क में नालों में बह रहे सीवरेज की बदबू ज्यादा थी। ऑक्सीजन लेवल कम था। इसके बाद यहां बांस और खस के पौधे लगाने का निर्णय लिया गया।

1500 वीआईपी करते हैं वॉक

- 26 हेक्टेयर में फैला है लिंक रोड-3 पर बना एकांत पार्क।
- 1500 से 2500 लोग रोज सुबह-शाम घूमने आते हैं।
- बारिश में 300 से 500 हो जाती है घूमने वालों की संख्या।
- विभिन्न प्रजाति के करीब तीन हजार पेड़ यहां पर लगे हैं।
- योग हट, 9 ट्रैक और 4 किमी का अंदरुनी वॉक ट्रैक बना।

बांस से आस

गुप्ता ने बताया कि ऐसे ही नालों के किनारे करीब 3 हजार बांस के पौधे लगाए जाएंगे। यह पानी के किनारे तेजी से बढ़कर मिट्टी के क्षरण को तो रोकेगा ही बड़े पेड़ होने पर नाले और वॉक ट्रैक के बीच परदे का काम भी करेगा। चूंकि बांस सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है तो यहां का ऑक्सीजन इंडेक्स बढ़ेगा। यह विंड ब्रेक का भी काम करेगा। इससे नालों से आने वाली बदबू रुक जाएगी। गुप्ता ने बताया कि विंड ब्रेक तकनीक का सबसे ज्यादा उपयोग यूरोपीय देशों में बर्फीली हवाओं को रोकने किया जाता है।

खस की खासियत

पर्यावरण वन मंडल और सामाजिक वानिकी के सीसीएफ एचसी गुप्ता ने बताया कि खस में कई तरह की खासियत देखने मिलती हैं। इसका हजारों सालों से तेल निकालने और खुशबू के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसमें मिट्टी में मिलने वाले और पानी में घुलनशील हैवी मैटल को सोखने की क्षमता है। एकांत पार्क के 3 नाले के किनारे खस के 3 हजार से पौधे लगाए जा रहे हैं।

सीएनजी से चलाते हैं अपनी कार और ट्रैक्टर

शुजालपुर में बायोगैस प्लांट से बनाई बिजली,

गोबर से 'गैसगुरु' बन गया 8वीं पास किसान

शुजालपुर। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के शुजालपुर के पटलावदा के किसान देवेंद्र परमार। आठवीं पास हैं। 100 दुधारू पशुओं का पालन करते हैं। देवेंद्र ने खेत में बायोगैस संयंत्र लगाया है। इससे वह न केवल अपने वाहन दौड़ा रहे हैं, बल्कि केंचुआ खाद के साथ बिजली भी पैदा कर रहे हैं। इस प्लांट से रोज 70 किलो गैस का उत्पादन हो रहा है। इसे वह सीएनजी के रूप में वाहनों में उपयोग कर रहे हैं। साथ ही, 100 यूनिट बिजली पैदा हो रही है। केंचुआ खाद बेचकर वह रोजाना 3 हजार और दूध बेचकर 4000 रुपए कमाई कर रहे हैं। इस तरह महीने भर में करीब 2.10 लाख की कमाई कर रहे हैं। सालाना करीब 25 लाख रुपए की इनकम हो रही है। जागत गांव हमार बता रहा है कि किसान को ये आइडिया कैसे आया और कैसे खुले आय के द्वार।

किसान के पास 7 बीघा जमीन है। बीते 4 साल से रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया। 100 दुधारू पशु हैं। रोजाना 25 क्विंटल गोबर जमा होता है। ऑटोमैटिक मशीन से गोबर 100 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में डाला जाता है। इससे 100 यूनिट यानी 12 किलोवाट बिजली पैदा हो रही है। गोबर के वेस्ट से केंचुआ खाद बनता है। 300 किलो जैविक खाद 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं। खाद को आसपास के गांवों के किसान ही ले जाते हैं।

हर महीने दो लाख की कमाई

किसान ने बताया, रोजाना 3000 हजार रुपए की जैविक खाद बेचता हूं। यानी महीने में 90 हजार की खाद बेच देता हूं। 500 लीटर दूध स्वयं के मवेशियों से और 1500 लीटर अन्य गांवों से कलेक्शन कर सांची दुग्ध संघ भोपाल को बेचकर रोज 4000 रुपए की कमाई हो रही है। अतिरिक्त बिजली के लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा रखा है।

खेत पर बन रही सीएनजी गैस

देवेंद्र ने बताया कि 2500 किलो गोबर से चलने वाले बायोगैस संयंत्र में बनने वाली गैस में 60 फीसदी मीथेन और 40 फीसदी कार्बन डाइ ऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाई ऑक्साइड को पानी व ऑयल से प्यूरीफायर करते हुए अलग किया जाता है, जिसमें पानी के साथ कार्बन डाई ऑक्साइड एक पाइप से बाहर निकल जाती है। दूसरे पाइप से मीथेन गैस बैलून में आ जाती है। इसी गैस को कंप्रेसर से वाहनों में सीएनजी के रूप में उपयोग कर डालते हैं। डीजल से ज्यादा 15 किमी प्रति किलो का ऐवरेज देती है।

ऐसे आया आइडिया

मेरा डेयरी का व्यवसाय है। आसपास के गांव से दूध खरीदकर लोडिंग वाहन, कार और ट्रैक्टर के जरिए लाते हैं। रोज 3 हजार का डीजल और पेट्रोल डलवाना पड़ता था। इस खर्च से परेशान होकर खुद के गोबर गैस के संयंत्र को बायोगैस प्लांट के रूप में कनेक्ट कराया। बिहार से आए इंजीनियर ने प्लांट लगाने में मदद की। इसमें 25 लाख की लागत आई। अब प्लांट से खेत में ही बैलून में रोज 70 किलो गैस का उत्पादन हो रहा है। इससे सीएनजी के रूप में उपयोग कर बोलेरो पिकअप वाहन, ऑल्टो कार और ट्रैक्टर और बाइक बिना खर्च के चला रहा हूं।

खेती बंद, मवेशियों के लिए चारा

देवेंद्र ने बताया, मेरे पास सात बीघा भूमि है। मैं परंपरागत उपज नहीं लेता हूं। हर दिन 500 लीटर दूध का उत्पादन देने वाले 100 दुधारू मवेशियों को खिलाने के लिए चारे की बोवनी करता हूं। चार साल से खेतों में रसायन का उपयोग का बंद कर दिया है। चारा भी जैविक खाद से ही पैदा कर रहा हूं। मवेशियों के लिए व्यवस्थित बनाए गए शेड में इस तरह नालियां और कंप्रेसर फिट किया गया है, जिससे गौमूत्र और गोबर ऑटोमैटिक संयंत्र चंद मिनटों में चला जाता है। मवेशियों को दिया जाने वाला चारा काटने से लेकर उन्हें दूध बढ़ाने के लिए दिए जाने वाला दाना बनाने की मशीन भी खेत पर लगा रखी हैं। यहां सिर्फ 5 मजदूर काम करते हैं।

सोयाबीन फसल के विपुल उत्पादन के लिए दी सलाह

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बी.एस. किरार साथ ही केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ.एसके जाटव, डॉ.आईडी सिंह एवं जयपाल छिगारहा द्वारा किसानों के खेतों पर भ्रमण कर सोयाबीन फसल के विपुल उत्पादन के लिए तकनीकी सलाह दी गई। सोयाबीन फसल के कम उत्पादन के कई कारण हैं, जैसे कि खरपतवार, कीट एवं बीमारियों आदि का समय पर उचित प्रबंधन ना करने पर फसल का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खरीफ फसलों में नीदा सबसे बड़ी समस्या है। जिसका समय पर उचित प्रबंधन हेतु निराई गुड़ाई करना या नीदानाशक दवा प्रयोग कर 15 से 25 दिन के अंन्दर फसल को नींदा रहित कर देना आवश्यक है। शाकनाशी दवा खड़ी फसल में बुवाई के 15 से 20 दिन बाद इमेजाथापर 400 मिली या क्यूजालोफांप पी. ईथाइल 400 मिली या फिनोक्फांप पी. ईथाइल 400 मिली एकड़ की दर से 200 लीटर पानी का घोल बनाकर बनाकर स्प्रेयर पंप फ्लैट फैन नोजल के माध्यम से छिड़काव करें।

15 अगस्त तक किसान स्वयं अपनी फसल की जानकारी कर सकेंगे दर्ज

-एमपी किसान एप पर मिलेगी सुविधा, पटवारी करेंगे सत्यापन

भोपाल। प्रदेश के किसान अब अपनी फसल की जानकारी स्वयं एमपी किसान एप पर दर्ज कर सकेंगे। एक से 15 अगस्त तक किसानों को यह सुविधा मिलेगी। किसान फसल की जो जानकारी देंगे, उसका पटवारी से सत्यापन कराया जाएगा। इसका उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने, कृषि ऋण देने सहित अन्य योजनाओं में किया जाएगा। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक पटवारी किसान की फसल की जानकारी एमपी किसान एप पर दर्ज करते थे। प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर सर्वे के समय एप में दर्ज जानकारी के मिलान में गड़बड़ियां सामने आती थीं। इसे देखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है कि किसान स्वयं अपनी फसल की जानकारी दर्ज करेगा। इसका सत्यापन पटवारी से कराया जाएगा। इसमें असहमति की स्थिति होने पर किसान खेत में उपस्थित होकर फोटो भी एप पर दर्ज कर सकेंगे। इससे वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, वंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)